स्टाक रखने के प्रभार और वितरण लागत शामिल होती है। 1995-96 से 1997-98 के दौरान इन घटकों पर प्रति क्विंटल खर्च और गेहूं और चावल की प्रति क्विंटल इकनामिक लागत निम्नानुसार है:-

(दर रुपये प्रति क्विंटल)

		1995-96	1996-97 (अनंतिम वास्तविक)	1997-98 (संशोधित अनुमान)
गेहूं				
(1)	अनाजों की एकीकृत लागत	351.04	381.62	494.42
(2)	वसूली प्रासंगिक खर्चे	89.70	101.96	107.69
(3)	राज्य एजेंसियों को स्टाक रखने के दिए गए प्रभार	30.61	41.51	22.77
(4)	वितरण लागत	112.60	115.06	175.62
(5)	इकनामिक लागत: (क + ख)	583.95	640.15	800.50

(दर रुपये प्रति क्विंटल)

		1995-96	1996-97 (अनंतिम वास्तविक)	1997-98 (संशोधित अनुमान)
चावल				
(1)	खाद्यान्नों की एकीकृत लागत	581.38	627.99	686.75
(2)	वसूली प्रासंगिक खर्चे	54.10	61.41	64.15
(3)	वितरण लागत	127.34	158.29	189.50
(4)	इकनामिक लागत	762.82	847.69	940.40

गेहूं की खरीद

2006. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा गेहूं की खरीद जून के पहले सप्ताह तक जारी रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो जून, 1998 के पहले सप्ताह तक गेहूं की कितनी खरीद की गई थी;

(ग) मार्च, 1998 में सरकारी गोदामों में उपलब्ध गेहूं की कुल अनुमानित मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उपलब्ध स्टाक की मात्रा तथा नई फसल की नई खरीद को ध्यान में रखते हुए भविष्य में गेहूं आयात करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो गेहूं की कितनी मात्रा का आयात किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, हां। रबी विपणन मौसम, 1998-99 के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य वसूली एजेन्सियों द्वारा गेहूं की वसूली अभी भी की जा रही है।

(ख) जून,1998 के पहले सप्ताह तक 121.00 लाख टन गेहूं की वसूली की गई थी।

(ग) पहली मार्च और पहली अप्रैल, 1998 को स्थिति के अनुसार सरकारी एजेन्सियों के पास केन्द्रीय पूल में उपलब्ध गेहूं की अनुमानित कुल मात्रा क्रमश: 59.52 लाख टन और 50.75 लाख टन थी।

(घ) और (ङ) सरकार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति की निर्धारित बफर मानदण्डों, देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, वसूली की प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यकता, खुले बाजार मूल्यों आदि की तुलना में निरंतर समीक्षा करती है और खाद्यान्नों के आयात का निर्णय समूची स्थिति के आधार पर लिया जाता है। वर्ष 1997-98

(रबी विपणन मौसम 1998-99 के दौरान विपणित) के दौरान देश में गेहूं उत्पादन की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने 20 लाख टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया। सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकार के प्रति 1998-99 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने आस्ट्रेलिया से 15 लाख टन गेहूं के ठेके किए हैं। फिलहाल सरकार ने प्राधिकृत शेष 5 लाख टन मात्रा का आयात नहीं करने का निर्णय लिया है।

सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार के अध्यक्षों को आवास प्रदान के लिए नियम

2007. **श्री चुन्नी लाल चौधरी:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार आदि जैसे संगठनों के अध्यक्षों को आवास प्रदान करने के लिए कोई मापदण्ड है; और

(ख) वे किस श्रेणी का आवास पाने के लिए हकदार हैं और सरकार किराए के रूप में कितनी राशि का भार उठा सकती है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Supply of Sugar through PDS

2008. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that supply of sugar through PDS will run out from mid-July this year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) Government's plan to revive it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) to (c) No, Sir. With the carry over stocks of the last season 1996-97 and the estimated production of sugar during the current sugar season 1997-98, the Central Government have already made allocations of levy sugar for Public Distribution System till August, 1998.

Adverse effects of Vanaspati import from Nepal

2009. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Vanaspati units in Eastern region are adversely affected on account of import of Vanaspati from Nepal under Indo-Nepal Treaty, as the imported Vanaspati is much cheaper in comparison with the indigenous production; and

(b) whether Government propose to amend the said Treaty so as to save the domestic industry; and if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is being taken up with the Government of Nepal in the contest of the provisions of the Treaty.

Measures for Controlling Prices of Essential Commodities

2010. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the prices of pulses, edible oils and other essential commodities have increased manifold since the past few months:

(b) if so, whether Government have totally failed to check the prices of essential commodities; and

(c) if so, the reasons therefor and further action Government propose to take to bring down the prices of essential commodities?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF FOOD (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) A statement showing the percentage variation in the wholesale price index of pulses, edible oils and certain other essential commodities for the last three months is enclosed. (*See* below).

(b) and (c) The Government has accorded the highest priority to the control of prices of essential commodities. Apart from certain long term measures to increase the production of essential goods, imports under Open Gen-